भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4
दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना

4. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अपनी अग्रणी जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक भारत में सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी 'हर घर जल' पहल के अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अप्रैल, 2024 तक केवल 75 प्रतिशत गांवों के घरों में ही पेयजल पहुंचाने वाले नल के लगने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस योजना को लागू करने में हाल ही में कुछ राज्यों में तेजी आई है, जबकि इस योजना की घोषणा काफी पहले वर्ष 2019 में ही कर दी गई थी; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पेयजल प्रदान करने के लिए, भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। जल राज्य का विषय है और इसलिए नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, 17.07.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 9.35 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल

जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 17.07.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 12.58 करोड़ (64.6%) परिवारों के घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

6 राज्यों - गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना और 3 संघ राज्य क्षेत्रों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली और दमण व दीव ने 100% कवरेज की सूचना दी है। कुल मिलाकर, देश के 140 जिलों और 1.72 लाख से अधिक गांवों में 100% कवरेज की सूचना दी गई है। कार्यान्वयन की गति में भी काफी सुधार हुआ है, और 1 जनवरी 2023 से, औसतन, देश में हर सेकंड एक से अधिक नल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जेजेएम के तहत व्यय भी 2019-20 में 10,065.87 करोड़ रुपये से उत्तरोत्तर बढ़कर 2020-21 में 20,345.39 करोड़ रुपये, 2021-22 में 44,204.23 करोड़ रुपये और 2022-23 में 91,268.58 करोड़ रुपये हो गया है। जेजेएम के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि से भी कार्यान्वयन की बेहतर गति स्पष्ट है।

हालांक, कुछ राज्यों ने आयोजना चरण में उनके सामने आने वाली कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण प्रारंभिक वर्षों में धीमी प्रगति की सूचना दी। कोविड-19 महामारी ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया। तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की गति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार सलाह दी जा रही है कि वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और तेजी लाएं। देश भर में मिशन के समयबद्ध कार्यान्वयन को गति प्रदान करने और राज्यों की सहायता करने के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वेबिनार, फील्ड दौरों आदि सहित इस विभाग में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्चतम स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

*****